



दैनिक भारतीय बस्ती

"युझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 2 मई 2026 शनिवार

सम्पादकीय

मरीज, आईसीयू और अदालत

अस्कर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि देश के किसी भाग में किसी निजी अस्पताल के आईसीयू में मरीज मरिजा के ठीक होने या ठीक होने की संभावना के बावजूद उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। वजह होती है कि अस्पताल का अनवरत गति से चलने वाला कामाई का मीटर। निरसंदेह, आधुनिक चिकित्सा खर्चीली और और बेहतर सुविधाओं के लिए बड़ी रकम चुकानी होती है। लेकिन इस व्यवस्था का मानवीय व संवेदनशील होना अपरिहार्य है। इसके निरामन का कार्य वृत्त तो देश के नीति-निर्माताओं और शासन-प्रशासन को करना चाहिए था। लेकिन विडम्बना यह है कि अदालत को ऐसे मामलों में पहल करनी पड़ती है। हाहा ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समान नमूना चिकित्सा इकाई डिस्चार्जित होने की जरूरत बनाया विवेकगतिव्यो से जुझती आईसीयू प्रणाली के लिए एक आशा की किरण लेकर आई है। इन डिस्चार्जितों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि चिकित्सकीय रूप से स्थिर हो चुके या जिन मरीजों के अंगों को बाहरी सहायता अथवा शारीरिक निगरानी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अस्पताल से छुड़ी दे दी जानी चाहिए। उन्हें अपना सामान्य बाड़ी में स्थानांतरित किया जा सकता है। निश्चित रूप से न्यायालय के ये निर्देश चिकित्सकीय और नैतिक दोनों हैं। जो बताते हैं कि जरूरी न होने के बावजूद मरीज को लंबे समय तक आईसीयू में रहना अनुचित है। यह एक हकीकत है कि मानकीकृत आईसीयू प्रोटोकॉल के अभाव में एक अस्पष्ट स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज से जुड़े निजी अस्पतालों का शिकार होकर बड़ जाते हैं। वास्तव में आईसीयू में मरीज मरीजों के तिनगारवादी को विस्थापित प्रक्रिया की गहन जांचकर अखर नहीं होती है। ये केवल चिकित्सक को डिस्चार्ज-निर्देशों पर ही निर्भर होकर बड़ जाते हैं। यही वजह है कि अस्पताल प्रबंधन के रहमों-करम पर मरीज को महंगे आईसीयू में लंबे समय तक नहीं रहने को मजबूर बनाया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि महान चिकित्सा कक्ष में मरीज रहने के बावजूद मरीज को उपचारहीन लगाने मिल रहा होता है। सही मायना में सुभीत करने के ये दिशानिर्देश एक सरल व सामान्य सिद्धांत की पुष्टि करते हुए इस विवेकगति को दूर करने का प्रयास करते हैं कि किसी भी अस्पताल का आईसीयू मरीज की अनिश्चितकालीन देखभाल के लिए नहीं होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शीघ्र अदालत ने समस्या के यथोचित समाधान की जरूरत पर बल दिया है। अदालत ने डॉक्टरों की प्रविष्टि को संरक्षित करने हुए चिकित्सा संस्थानों व अस्पतालों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया है। इस दिशा में व्यवस्थागत मुद्दों पर जोर दिया गया है, जिसमें नर्स व मरीज के अनुपात, विशेषज्ञ पर्यवेक्षण, मानक बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कराना एक सराहनीय पहल कही जाएगी। निश्चित रूप से भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में भारी असमानता है, ये न्यूनतम मानादंड अधिक न्यायसंगत देखभाल के लिए आधार बन सकते हैं। सही मायना में पराम्यो और केंद्रशासित प्रदेशों को प्राथमिकता बांट होना की पहचान करने और समबद्ध कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही निर्देश नीति के क्रियान्वयन हेतु तुरन्त दिशानिर्देश चाहिए। लेकिन विराट के अनवरत बताते हैं कि एक अच्छे डिस्चार्ज वाली कार्ययोजना तब अपने लक्ष्य पाने में विफल हो जाती है जब उसका क्रियान्वयन अर्धे-अधुरे ढंग से किया जाता रहा है। निश्चित रूप से निगरानी ढांचे और समन्वित राष्ट्रीय स्तर की कार्यवाही पर अदालत की पहल सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसकी अनुपालन की संकलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, विवेक बोधन और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करेगी। साथ ही दस्ता के अन्तर्गत, मानवीय पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। विराट चिकित्सा कक्ष में लंबे समय तक नहीं रहना मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़े कष्टदायक होता है। स्थिर मरीजों को कम तरफ पर देखभाल की जरूरत वाले बाड़ों में स्थानांतरित किए जाने से न केवल आवश्यक चिकित्सा खर्च बचता है। बल्कि यह मानवीय पुष्टिकोण का भी प्रतिकार है। निश्चित रूप से आईसीयू के लिए एकसमान मानादंड लागू करने का प्रयास भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने और सर्वसंगत निर्णय लेने को बढ़ावा देने वाला साक्षित हो सकता है।

जहरीला भाषण और तंत्र

पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश की राजनीति में लोगों के बीच नजरत फिलाने वाले भाषण या मडकाउ भाषणों के जरूरि सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने की कोशिशें चिता का कारण बनती रही हैं। ऐसे अनेक कौम समाने आए, जिनमें किसी नेता पर राजनीतिक स्वार्थ संचालने या कायदा उल्लंघन की मंशा से ऐसी सदनवाचिकाएँ करने या नारे लगाने के आरोप लगे, जिससे सामाजिक समानता-विचारों की आक्रान्ता पैदा हुई। मगर ऐसे नेताओं को जहां कानून के कवच पर सदा कड़ा किया जाना चाहिए था, वहां उनका प्रति पुलिस या शासन-तंत्र ने एक सख्त जेठ से नरम जवाब अनायास।

शायद इन्हीं बड़ाब से सुभ्रित कर्तव्य है एक याचिका दायित्व कर बढाने नकरती भाषणों की समस्या से निपटने के लिए डिस्चार्जित मरीजों की जरूरत की गई थी। मगर इस मसले पर सुचारुवर्ध के बाद अदालत ने कहा कि वेदमन कानून का ढांचा लोगों के बीच दुस्मनी को बढ़ावा देने, भाँकिक भावनाओं को तेज पहुँचाने या सांजजनिक शांति को भंग करने वाली हरकतों से बचना तैयार हो सकता है। इसमें भारतीय दंड संहिता और अन्य संसदीय कानूनों को प्राकृप्त शामिल है।

जाहिर है, मौजूदा कानूनी प्रक्राओं के संदर्भ में अदालत ने एक तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है। मगर इससे इतर मरिजादी भाषणों को जरूरि अपरिहार्य के बीच इतिवृत्त फेराने की कोशिश की जाती है। तो उसकी की जरूरि सिर लेने व्याख्या करने और उसका कानूनी दायरे में लाने की जरूरत है। इस संदर्भ में अदालत ने स्पष्ट किया कि अपराध की व्याख्या या उसे परिभाषित करना और सजा तब करना पूरी तरह विधिगतिक के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में अदालत केवल सुचारुवर्ध की जरूरत की और विचारक और कार्यपालिका का ध्यान खींच सकता है।

अदालत की यह टिप्पणी अहम है कि निष्कर्षी भाषणों के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं की शिकायत कानून के अभाव में नहीं, बल्कि उसके लागू होने में कमी से पैदा होती है। ऐसी शिकायतें अना रही हैं कि कानूनी प्रक्राओं के अभाव के बावजूद कई मामलों में पुलिस या तो आरोपों की अनदेखी करती है या फिर कजवाले धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है। नतीजतन, जिन नासिद्धि की कमी से आरोपी को विवेकान संरक्ष करवाई जाती होती है, उसके विवेक कानून चलाकर नजर आता है।

दरअसल, हाल के वर्षों में कुछ नेताओं ने न केवल लोगों की भावनाएं मडकाने वाले भाषण दिए, बल्कि इस बात का खयाल रखा भी जरूरि नहीं समझा कि इससे देश में अलग-अलग मसुदाओं के बीच संभारना को गुंथाना पड़च सकता है और विचार हालात भी पैदा हो सकता है। मगर ऐसे अपविष्टक भाषण देने वाले लोगों के विवेकान दोषकारक करने को लेकर सरकारों के भीतर ईमानदार इच्छाशक्ति का अभाव दिखाई देता है। यह खयाल मरीजों की जरूरत है कि इस तरह की प्रवृत्ति की अनदेखी करने या सुविधानाक तरीके से कुछ नेताओं के नकरती भाषणों के प्रति आसक्त मुद्दे लाने का न्यूनतम आधिकारिक अना जनाता और देश को उठाना पड़ेगा।

कुछ अदालत ने ही इन्हीं संधियों में कहा कि मरिजादी भाषण और अपवाह कर्तव्य से जुड़े मुद्दे सीधे तौर पर भाईदर, पारदर्शिता और सौजनिक व्यवस्था को संरक्षण से जुड़े हैं। कायदे से कुछ संवेदनशील स्थितियों के बावजूद अगर मौजूदा कानूनी प्रक्राओं का दायरा सीमित है, तो यह केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर है कि बदलते परिस्थित तथा चुनौतियों के मद्देनजर आगे किसी दोस कानूनी उपाय की जरूरत पर विचार करें।

विकास का एक्सप्रेस वे बनेगा गंगा एक्सप्रेस वे

—मृत्युंजय दीक्षित—

उत्तर प्रदेश में अवस्थापना विकास के क्रम में निर्मित गंगा एक्सप्रेस वे आम जनमानस के लिए खुल रहा है जिसे प्रदेश के विकास में मील का पत्थर माना जा रहा है। 594 किमीकी तरह लंबा गंगा एक्सप्रेस वे प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने वाला पहला सीधा हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है। इस परियोजना पर 36.20 करोड़ की लागत आई है। यह एक्सप्रेस वे मेरठ के बिजौली गाँव से प्रारंभ होकर बुन्देलखर, हापुड, अमरोहा, शाहजहांपुर, संजय, बंसपुर, उन्नाव, हरदोई, प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए प्रयागराज जिले के जुजुपुर दक्षिण तक जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के प्रारंभ हो जाने के बाद देश के एक्सप्रेस वे नेटवर्क में गूणी की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत हो जाएगी और परिव्योजनाओं की कुल लंबाई 1910 किमी हो जाएगी। छह लेन का यह एक्सप्रेस वे पूरी तरह त्रिभुजाकार व एक्स-क्रेडोलाइन इन्वर्न 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड, 17 टोल प्लाजा 8 मुख्य पुल और 381 अडवापस शामिल है।

यह भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे जिस पर होटल, ढाबा और ईवी चार्जिंग स्टेशन से लेकर अस्पतालों तक बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेस वे पर विश्वस्तरीय फुट वेन और मोटेल तक की सुविधाएं मिलेंगी। 594 किमी लंबे इस एक्सप्रेस वे का 80 प्रतिशत निर्माण अडानी इंटरप्राइजेज ने किया है।



अडानी ने प्रयागराज से बदायूं तक 464 किमी लंबा एक्सप्रेस वे बनाया है जबकि शेष 20 प्रतिशत आईआरसी इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाया है। एक्सप्रेस वे माल्टेन्सनेमल चैन भी उपलब्ध— एक्सप्रेस वे पर लखनऊ के खानपान और चिकनकारी की अन्नक दियार्ड पंडेगी। इस वे पर एक बड़ा इन्वर्न 6.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड, फुल्टी बार किसी एक्सप्रेस वे पर टूक होने वाला गंगा है। मोटेलों की सुविधाओं से लैस यह एक्सप्रेस वे प्रदेश की कनिस्ट्रेटडटी के परिदृश्य को बदलकर रख देगा।

यसुना के लिए अहम बरगा एक्सप्रेस वे— यह एक्सप्रेस वे नागरिकों का सफर आसान बनाने के साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत भी बनने वाला है। एक्सप्रेस वे पर शाहजहांपुर के जलालाबाद में बच्चों के लिए विल्डन ले एरिया

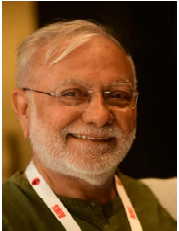
3.5 किमी की हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। आगतकालीन स्थिति व मुद्दे होने पर रणनीतिक तौर पर यह बड़ा पट्टी लड़ाकू विमानों के उतरने व उड़ान भरने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकेगी। इस हवाई पट्टी का निर्माण मनी प्रकार के लड़ाकू विमानों के उतरने के इतिहास से किया गया है। इस पर राफेल सुखोई-0 एम्केआई मिनाज 2000 जनुआर और मिंग 29 जैसे लड़ाकू और सी-130 जे सुपर हक्युलिंस और एएन-32 जैसे वायुसेना के विमान उतरने के साथ-साथ उड़ान भी भर सकेंगे। इस पर रात में भी लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान भरने की सुविधा होगी। इसके लिए एक्सप्रेस वे पर प्रीजिजन आरिथ लाइटिंग सिस्टम व उन्नत नैविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही शार्प डेटेसिटी रनवे लाइटिंग

का उपयोग किया गया है। हवाई पट्टी की सुखा के लिए 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो किसी भी आपातकालीन स्थिति पर नजर रखने के लिए सहायक रहेंगे। इस एक्सप्रेस वे का संचालन पूरी तरह आत्मो को जाने के बाद 12 जिलों के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी जिससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा पलायन कम होगा। प्रदेश सरकार की योजना इससे किनारे 27 औद्योगिक बस्तुदर बनाने की है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और आवंटन चल रहा है। इससे रसद आपूर्ति, खाद्य प्रसंकरण वस्त्र उद्योग और वित्तीय क्षेत्र को कई उर्जा मिलेगी। मेरठ के खेल उद्योग, हापुड के स्थचकार, बंसपुर के जरी जरदोजी और प्रयागराज के कृषि उत्पादों को अब दिल्ली और पूर्वांचल के बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा। प्रमुख विशेषता— इस एक्सप्रेस वे की पूरी सड़क पर जल संवर्धन प्रणाली लगाई गई है ताकि वर्षा का जल सीधे जमीन के अंदर जाए और भूजल स्तर पर बना रहे। यह भारत का सबसे लंबा निरंतर प्लाचल्ट प्रवेश एक्सप्रेस वे है जहां आमत पशुओं को स्थचरिया यातायात के अनिवार्य प्रवेश को पूरी तरह से रोका गया है। यह परियोजना आराम की इन्जीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके निर्माण में भारी मात्रा में संयोजे की रास का उपयोग किया गया है जो प्रदूषण कम करने में सहायक है। पहले स्मॉलएर नैविगेशन के किनारे बस्ती भी किंगु अर एक्सप्रेस वे के किनारे होती है इस ध्यान में

रखते हुए एक्सप्रेस वे किनारे 18 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण की गुणवत्ता को एक्सप्रेट रेटिफिग मिली है। विशिष्ट सुखा तकनीक भी— यहां पर विशिष्ट सुखा तकनीक का प्रयोग किया गया है। सड़क के दोनों किनारों पर हाइड एल्टेड स्ट्रिप लगाई गई है। यदि किसी चालक को झपकी आ जाए और वाहन इन स्ट्रिप पर चढ़ जाए तो तेज कंपन और आवाज पैदा होगी जिससे चालक तुरंत सतर्क हो जाएगा और दुर्घटना टल जाएगी। इस सड़क पर चलने के दौरान श्रद्धेय और कंपन महसूस नहीं होगी। मंदिर आर्थिकी व पर्यटन को भी मिलेगी— गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण होने के बाद अब मंदिर आवासीय आर्थिकी व पर्यटन को भी मिलेगी। यह एक्सप्रेस वे बाजा को ही आसान नहीं करेगा अपितु प्रदेश में आर्थिक व भाँकिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। 12 जिलों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेस वे से समुख आवासीय व भाँकिक स्वल जुड़ रहे हैं। इसमें गडमुशुबर, कच्छ धाम, वेल्हा देवी आदि प्रमुख चिकित्सा स्थिति पीठ और डिस्चार्जि प्रवेश शामिल हैं। एक्सप्रेस वे शुरू हो जाने के बाद श्रद्धालु इन तीर्थों के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। आरामी समय में वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र तक इस्का विस्थापन किया जिससे वाराणसी, विस्थापन और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी।

— मृत्युंजय दीक्षित (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं)।

कारपोरेट व्यवस्था में श्रमिक हितों के संरक्षण की जरूरत



—इन्द्रजीत सिंह—

एक मई को सभी देशों के श्रमिक इकट्ठे होकर शोषण, उद्वेगन व अन्याय वाली व्यवस्था में बदलाव कर सामंताता का लक्ष्य आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। अपनी एकता प्रदर्शित करते हैं जो नये आम कानूनों व श्रमिक हितों की मौजूदा चुनौतियों के चलते और अधिक महत्वपूर्ण है। इस साल मई दिवस यानी मजदूर दिवस अमृतसर परस्थितियों में आया है। वहीं दिनों राष्ट्रीय राजधानी के बाँरों और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक संसदों सहितों पर प्रकट हुआ। अंतोमनोबाहिर, गारमेट जैसे उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की प्रमुख मांगें न्यूनतम वेतन में बढ़ती और अधिक प्रतिदिन आउट घंटे से ज्यादा काम लेने पर सैल्यूना ओवरटाइम थी। ऐसी मांगों को शायद ही कोई अनुचित कष्ट रहे। लेकिन मजदूर, गुंडावा, भिषाड़ी और नोएडा में फूट आरंभों को शांत करने के लिए श्रमिकों की सुविधाई करने की बजाय उन पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया। कई गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। पिछले दिनों ऐसी ही स्थिति पणपत रिफाइनरी के श्रमिकों के असंतोष के रूप में सामने आयी।



शासन-प्रशासन की ओर से श्रमिकों के इस स्वतःकपूर्व असंतोष के पीछे कथित संधिगत ताकतों का हथ धक्का पूरे मामले को रसमय्य बनाने की कोशिश की। लेकिन असंतोष अभी भी कायम है। वहीं उर्जा संकट के कारण गुजरात जैसे प्रदेशों से मजदूर पलायन कर गए हैं। इस ताजा दुःखानुभव के विस्तार के इतिहास से पहले एक नजर मई दिवस के ज्ञानेय पर उड़ाना जरूरी है। मई दिवस की शुरुआत साल 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में मई महीने के पहले सप्ताह में हवाई अड्डाकिल मजदूरों द्वारा की गई होडालिग से हुई थी। सत्रकों पर आकर 8 घंटे का कार्य दिवस और कार्यस्थल पर सम्मानजनक व्यवहार की मांग को लेकर रोष प्रदर्शनों से निपटने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में कुछ मजदूर शहीद हुए। बाद में हिंसा फैलाने के मगनदंत

परिवर्तन, चुनौतियां और संभावनाओं का नया युग



—पंकज यादव—

आज का समाज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहाँ परिवर्तन केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन का स्थायी स्वरूप बन चुका है। विज्ञान और तकनीक की तीव्र प्रगति, सामाजिक संरचनाओं में बदलाव, आर्थिक प्रतिस्पर्धा का विस्तार और वैश्विक प्रगति का बदती पहुँच हमारे परिवेश को पहले से कहीं अधिक जटिल, गतिशील और बहुआयामी बना दिया है। यह परिवेश एक ओर अनुत्पन्न अवसर प्रदान करता है, तो दूसरी ओर अनेक गंभीर चुनौतियों को भी जन्म देता है। ऐसे समय में यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस परिवर्तनों को केवल स्वीकार ही न करें, बल्कि उन्हें समझते हुए उनका का आवाज उठाना स्वाभाविक हो जाए। बता दें कि नव-उदारवादी दौर में काफी देर के मुंब्यों के चलते वर्ष 2020 में सभी 29 अम कानूनों को हटाकर उनकी जगह पर बार आम सहिता (लेबर कोड) संसद में पारित किए गए। डेड यूनिवर्स के तथे विवेच के बावजूद 21 नवंबर 2025 में जारी लागू करके की अति सूचना नहीं कर दी गई।

देश की सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों का मानना है कि बार आम सहिता लागू होने की स्थिति में काम के तथे में वृद्धि होगी, यूनियनों का पंजीकरण करवाना कठिन होगा, हडताल करके पर डंडमन कारवाई की जा सकेगी, स्थाई रोजगार की बजाय टेक प्रणाली का प्रचलन बढ़ेगा और नती व अनामान आसान होगा। यही नहीं, 300 तक श्रमिक संख्या वाले उद्योगों को आम विभाग की अनुमति के बिना मजदूरों को हटाने की छूट रहेगी। इसके चलते आम विभाग निरर्थक होकर बड़ जाएगा वहीं श्रमिकों की स्थिति बंधुआ जैसी हो सकती है। लेबर कोड के पक्ष में जैसी दलीलें दी जा रही हैं ठीक वैसी ही तथे कानूनों के संबंध में भी वैसी ही जिन्हें आँलन के बाद का करण भी बन सकती है। इस्लरि आता आस्यकरकता इस बात की है कि तकनीक का सफा के रूप में अपनाया जाए, न कि उसे अपने ऊपर हावी होने दिया जाए। डिजिटल सारकार और जागरूकता को बढ़ावा

ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी गंभीर संकट का सामना कर रहा है। बढ़ता प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुँच चुका है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। नदियाँ का प्रदूषण और भूजल स्तर में गिरावट भीषण के लिए गंभीर चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य मौसम, बाढ़ और सूखा जैसी घटनाएँ बढ़ रही हैं। यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो सामाजिक भी तेजी से बदल रहा है। पहले जहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, वहीं अब एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को महत्व दिया जा रहा है, जो एक सकारात्मक परिवर्तन है। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ी है, जिससे समाज में लैंगिक समता की दिशा में प्रगति हुई है। किन्तु इसके साथ ही सामाजिक मुद्दों में गिरावट भी देखने को मिल रही है। परिवारिक संबंधों में दूरी, सुर्गों की उथल-पुथल और नैतिक मूल्यों का क्षरण चिंता का विषय है। और समाज के नाम पर कई बार हमारी संविधिक जड़ें कमजोर पड़ती दिखाई देती हैं। यह आवश्यक है कि हम परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करें। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए आधुनिकता को अपनाना होगा। प्रति समाज में स्थायित्व और संतुलन बना रह सकता है। आर्थिक दृष्टि से वर्तमान समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत जैसी उपरती अर्थव्यवस्था में स्टांडाईस संस्कृति, डिजिटल मूडान प्रवृत्तियों का कार्य विचार ने नए अवसरों को बढ़ा खोले हैं। युवाओं की नए-नए करिपर विकल्प सामने आ रहे हैं। हालाँकि, इस विकास के साथ-साथ असमानता भी बढ़ रही है। अमीर और गरीब के बीच की खाई गहरी हो चुकी है। रोजगार की कमी, कोशल की कमी और शिक्षा प्रणाली की सीमाएँ भी रोजगार की तथे में बाधा बन रही हैं। इस स्थिति में सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि वे कोशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दें, रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न करें और आर्थिक समता सुनिश्चित करने के लिए उदात्त उपायों को 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे प्रयास नहीं समझें होंगे जब हर वार्ड को विकास का समान अवसर मिलेगा। आज का परिवेश केवल सामाजिक और आर्थिक



